



# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## असाधारण भाग सात

वर्ष १०, अंक १४]

बुधवार, ऑगस्ट २८, २०२४/भाद्रपद ६, शके १९४६

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २८

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

### नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२,  
दिनांकित १६ अगस्त, २०२४।

### MAHARASHTRA ORDINANCE No. V OF 2024.

#### AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS,  
NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIP ACT, 1965.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ५ सन् २०२४।

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में  
अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं  
सन् १९६५ जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक  
का महा. नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;  
४०।

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्राप्ति। १. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०२४ कहलाये।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ३४१ख-१ में संशोधन। २. महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (जिसे इसमें आगे “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा ३४१ख-१ की उप-धारा (९) अपमार्जित की जायेगी और १ जनवरी २०२२ से अपमार्जित की गयी समझी जायेगी। सन् १९६५ का महा. ४०।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ३४१ख-२ में संशोधन। ३. मूल अधिनियम की धारा ३४१ख-२ की, उप-धारा (६) में, “ ढाई वर्षों की अवधि के लिये ” शब्दों के स्थान में, “ पाँच वर्षों की अवधि के लिये ” शब्द रखे जायेंगे और १ जनवरी २०२२ से रखे गये समझे जायेंगे।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ३४१ख-४ में संशोधन। ४. मूल अधिनियम की धारा ३४१ख-४ की,—  
(१) उप-धारा (१) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी और १ जनवरी २०२२ से रखी गयी समझी जायेगी, अर्थात् :—

“ (१) अध्यक्ष का पदावधि पाँच वर्षों का होगा और **नगर पंचायत** की अवधि के साथ समाप्त होगा । ”;

(२) उप-धारा (३) अपमार्जित की जायेगी और १ जनवरी २०२२ से अपमार्जित की गयी समझी जायेगी।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति। ५. (१) इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में, यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियमों के उपबंधों से कोई बात असंगत न हो, जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

**वक्तव्य**

महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का महा. ४०) में अन्तर्विष्ट **नगर पंचायतों** के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के निर्वाचनों संबंधी उपबंध, उसमें से निर्वाचित पार्षदों द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये और ऐसे पदाधिकारियों का अवधि ढाई वर्ष करने की दृष्टि से सन् २०२० का महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १२ द्वारा संशोधन किया गया है। सन् २०२२ का महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ के प्रारम्भण के पश्चात् लिये जानेवाले **नगर पंचायतों** के निर्वाचनों के संबंध में अध्यक्ष के सीधे निर्वाचन और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का अवधि पाँच वर्षों तक करने की दृष्टि से सन् २०२२ का महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ द्वारा उक्त अधिनियम में तद्नंतर संशोधन किया गया है।

२. सरकार यह उपबंध करना आवश्यक समझती है कि, अप्रत्यक्ष निर्वाचित **नगर पंचायतों** के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अवधि भी पाँच वर्षों का होगा। इसलिये, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ की धाराएँ ३४१ख-१, ३४१ख-२ और ३४१ख-४ में यथोचित संशोधन करने का प्रस्तावित किया गया है।

३. चूँकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने के लिये, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,

दिनांकित १५ अगस्त, २०२४।

**सी. पी. राधाकृष्णन,**

महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

**डॉ. के. एच. गोविंद राज,**

शासन के प्रधान सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),

**विजया डोनीकर,**

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।